

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)



सं. 205] No. 205] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 320(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्ते) दूसरा संशोधन नियम, 2000 है।
 - (2) ये 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भन्ने तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उपनियम (2) में "पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष" शब्दों से आरम्भ होकर "प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष के लिए चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे!

स्पष्टीकरण जापन

केंद्रीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन का पुनरीक्षण 1 जनवरी, 1996 से करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार उपनियम (2) के उपबंधों का भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से संशोधन किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. ए-11014(13)/98-एटी]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

- पाद टिप्पण: —मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का.नि. 1092(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए :—
 - (1) सा.का.नि. 424(अ) दिनांक 4-4-1998
 - (2) सा.का.नि. 1049(अ) दिनांक 13-12-1989
 - (3) सा.का.नि. 520(अ) दिनांक 13-11-1996
 - (4) सा.का.नि. 86(अ) दिनांक 3-2-2000

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

- G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) second Amendment Rules, 2000.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January. 1996.
 - 2. In rule 8 of the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the portion beginning with the words "rupees seven hundred per annum" and ending with the words "rupees three thousand five hundred per annum", the words "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 1996. Accordingly, the provisions of sub-rule (2) are being amended from a retrospective date that is 1st January, 1996. It is certified that no one is being affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

¡No. A. 11014/13/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secv.

- Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. G.S.R. 1092 (E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide notification Nos.—
 - (1) G.S.R. 424(E), dated 4-4-1988.
 - (2) G.S.R. 1049(E), dated 13-12-1989.
 - (3) G.S.R. 520(E), dated 13-11-1996.
 - (4) G.S.R. 86(E), dated 3-2-2000.